भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1462
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

कर्नाटक में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और सुलभता

†1462. **श्री बसवराज बोम्मई:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों और बुनियादी ढांचे की कमियों की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ग) छात्र नामांकन और अधिगम स्तरों के संदर्भ में प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): 'शिक्षा' विषय संविधान की समवर्ती सूची में है और देश के अधिकांश स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं।

केंद्र सरकार वर्ष 2018-19 से कर्नाटक सहित पूरे देश में स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना - समग्र शिक्षा लागू कर रही है, जिसमें प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा शामिल है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ा गया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, जिससे उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न

शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जा सके।

समग्र शिक्षा के तहत, कर्नाटक सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर पात्र बच्चों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें और यूनिफ़ोर्म, शिक्षण-अधिगम सामग्री, माध्यमिक स्तर तक परिवहन / एस्कॉर्ट सुविधा, स्कूल से बाहर बच्चों के आयु-उपयुक्त प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण, मौसम अनुरूप छात्रावास / आवासीय शिविर, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, आयु-उपयुक्त आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, एनआईओएस / एसआईओएस के माध्यम से शिक्षा पूरी करने के लिए स्कूल से बाहर बच्चों (आयु16 से 19) को सहायता, समग्र प्रगति कार्ड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को सहायता शामिल है।

इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों की अवसंरचना के विकास/सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, पीएम-जनमान के अंतर्गत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, अनुसूचित जनजाति की असंतृप्त आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत छात्रावासों के निर्माण सहित स्कूली शिक्षा की पहुंच में सुधार करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जैसा कि कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, गणिता गणका (वन टू वन, शिक्षक-छात्र, रिमोट फोन ट्यूशन जैसे विभिन्न कदम यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र गणित के बुनियादी कार्यों को समझते हैं), मारुसिंचना (अधिगम के अंतराल को सुधारने के लिए उपचारात्मक शिक्षण), ज्ञानसेतु (एआई सहायता प्राप्त ऐप जो विभिन्न विषयों में अतिरिक्त शिक्षण सामग्री को पूरा करता है) जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, स्कूल शिक्षा की पहुंच में सुधार करने के लिए उच्चतर प्राथमिक स्कूलों का माध्यमिक स्कूलों में स्तरोन्नयन किया गया है, दूरस्थ बस्तियों से आने वाले छात्रों को 100% परिवहन और मार्गरक्षण भत्ता प्रदान किया गया है।

(ख): शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और युक्तिसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आती है। इसके अलावा, भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है और रिक्तियां कई कारकों जैसे सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण शिक्षकों की बढ़ी हुई आवश्यकता आदि के

कारण उत्पन्न होती हैं। कर्नाटक सहित देश भर में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के रिक्त पदों से संबंधित आंकड़े संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रखे जाते हैं।

तथापि, यह विभाग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शिक्षा के लिए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडाइज़+) के माध्यम से प्रतिवर्ष शिक्षकों की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे आदि के बारे में जानकारी एकत्र करता है। अद्यतन यूडाइज़ + रिपोर्ट अर्थात् यूडाइज़ +2024-25 के अनुसार, कर्नाटक में सभी स्तरों पर सभी सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का विवरण इस प्रकार है:

कुल	प्राथमिक (1–5)	उच्च प्राथमिक (1–8)	उच्च प्राथमिक (6–8)	माध्यमिक (1–10)	माध्यमिक (6–10)	माध्यमिक (9–10)	उच्चतर माध्यमिक (1–12)	उच्चतर माध्यमिक (6–12)	उच्चतर माध्यमिक (9–12)	उच्चतर माध्यमिक (11-12)
1,95,656	36,209	98,157	257	8,463	8,179	25,420	1,948	2,272	10,204	4,547

यूडाइज़ +2024-25 रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता का विवरण इस प्रकार है:

	सरकारी स्कूलों का प्रतिशात (%)
लड़कों के लिए शौचालय वाले सरकारी स्कूल	95.8
लड़कियों के लिए शौचालय वाले सरकारी स्कूल	98.8
पेयजल वाले सरकारी स्कूल	99.9
रैंप वाले सरकारी स्कूल	87.8
बिजली वाले सरकारी स्कूल	98.9
खेल के मैदान वाले सरकारी स्कूल	82.0
बाउंड्री वाल वाले सरकारी स्कूल	89.7
पुस्तकालय/बुक बैंक/रीडिंग कॉर्नर वाले सरकारी स्कूल	99.1

(ग): अद्यतन यूडाइज़ +2024-25 रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में 47,34,360 छात्र नामांकित थे

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत आधारभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों (क्रमशः कक्षा 3, 6 और 9) के अंत में छात्रों के बीच दक्षताओं के विकास में आधारभूत प्रदर्शन को समझने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख, एनसीईआरटी द्वारा दिसंबर, 2024 में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 (पूर्व में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण) किया गया था। इस सर्वेक्षण को

भारत में अधिगम परिणामों पर एक प्रणाली-स्तरीय प्रतिबिंब के रूप में डिजाइन किया गया है जो स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण योग्यता, कौशल या बुनियादी ढांचे की कमी को रेखांकित करता है। कर्नाटक राज्य में छात्रों का कक्षा-वार समग्र प्रदर्शन निम्नानुसार है –

कक्षा	विषय	सही स्कोर प्रतिशत
कक्षा 3	भाषा	60
	गणित	57
कक्षा 6	भाषा	55
	गणित	45
	हमारे आसपास की दुनिया	47
कक्षा 9	भाषा	51
	गणित	33
	विज्ञान	37
	सामाजिक विज्ञान	37

****